राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2795

17 दिसम्बर, 2014 को उत्तर के लिए

भारतीय इस्पात अनुसंधान और प्रौद्योगिकी मिशन

2795. श्रीमती अम्बिका सोनी:
डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी और गैर-सरकारी इस्पात कंपनियों ने प्रस्तावित भारतीय इस्पात अनुसंधान और प्रौद्योगिकी मिशन (एसआरटीएमआई) के लिए सहभागी निधीयन सूत्र अभिनिर्धारित किया है ताकि यह मिशन इस उद्योग में अनुसंधान और विकास का नेतृत्व कर सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत में व्यापार की मात्रा का अनुमानित संयुक्त निवेश स्तर क्या होगा और क्या यह अन्तर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करता है; और

(घ) इस्पात उद्योग में अन्तर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए एसआरटीएमआई के कार्यों का प्रबंधन कौन करेगा?

उत्तर

इस्पात और खान राज्य मंत्री **श्री विष्णु देव साय**

(क) और (ख) : इस्पात मंत्रालय लोहा और इस्पात उद्योग में अनुसंधान एवं विकास कार्य की अगुआई के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की इस्पात कंपनियों के सहयोग से उद्योग संचालित एक स्टील रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी मिशन ऑफ इंडिया (एसआरटीएमआई) की स्थापना को सुगम बना रहा है। उक्त एसआरटीएमआई की स्थापना 200 करोड़ रुपए की आरंभिक निधि के साथ की जानी प्रस्तावित है, जिसमें इस्पात मंत्रालय और भागीदार इस्पात कंपनियों द्वारा योगदान किया जाएगा।

(ग) : विदेश में अग्रणी इस्पात कंपनियों में आरएंडडी पर वार्षिक निवेश उनकी कुल बिक्री टर्नओवर का 1 - 2 प्रतिशत तक होता है। भारतीय इस्पात संयंत्रों में आरएंडडी पर निवेश उनकी बिक्री टर्नओवर का 0.15 - 0.3 प्रतिशत तक होता है। एसआरटीएमआई की स्थापना होने और इसके अंतर्गत आरएंडडी परियोजनाएं क्रियान्वित होने से भारतीय इस्पात क्षेत्र में आरएंडडी निवेश में वृद्धि होने की संभावना है।

(घ) : एसआरटीएमआई के कार्यों का प्रबंधन एक शासी निकाय द्वारा किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की इस्पात एवं संबद्ध कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा वाले क्षेत्रीय विशेषज्ञ तथा इस्पात मंत्रालय का एक नामिति शामिल होगा। एमआरटीएमआई की कार्यकारी कार्यप्रणाली का संचालन एक निदेशक, जिसे सहायक कार्मिकों की सहायता प्राप्त होगी, द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।

*****